(ii) जनजातीय क्षेत्रों मे सभी एक्सचेंजो को आटोमेटिक बनाना ।

(iii) प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र मे सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करना ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे के अनुसार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार के जनजातीय क्षेत्रों मे जो दूर संचार सुविधाएं देने का प्रस्ताव है, उनका संक्षिप्त विवरण निम्न नुसार है :--

क्र०स०	मद	उड़ीसा	मध्य प्रदेश	बिहार
1.	निवल स्थानीय स्विचन क्षमता	21150	52000	19100
2	सीधी एक्सचेज लाइनें	14800	41700	18500
3.	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन	प्रत्येक ग्राम पचायत मे एक		

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को अनुदान

744 **श्री अजीत जोगी** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा केन्द्रीय सडक निधि के अंतर्गत 3 अक्तूबर, 1989 को केन्द्र सरकार के पास वर्ष 1989-90 तथा आठवी पचवर्षीय योजना के लिये 92 83 करोड रुपये के प्रस्ताव भेजे गये है ,

(ख) क्या मध्य प्रदेश शासन द्वारा 500 से अधिक जनसंख्या वाले आदिवासी ग्रामो को मुख्य मार्गों से जोडने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति/वित्तीय सहायता हेत् भेजा हैं ,

(ग) मध्य प्रदेश शासन को उक्त राशि उपलब्ध कराने हेत् केन्द्र सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिया जायेगा और यह राशि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी, और

(घ) क्या 500 से कम जनसख्या वाले आदिवासी ग्रामों को भी सडको से जोडने के बारे मे केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्री, साथ मे जल-भतल परिवहन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) जी हां ।

(ख) ग्रामीण विकास विभाग को, जो कि नॉडल मत्रालय है, ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है, तथापि, वे आदिवासी ग्रामों को जोडने के लिए कोई योजना नही चला रहे है।

(ग) चूंकि केन्द्रीय सडक निधि मे वास्तविक वृद्धि, जिसके आधार पर प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे, अभी नहीं हुई है इसलिए इन प्रस्तावो पर अनमोदन के लिए कार्यवाही नही की गई है ।

(घ) जी, नही ।

मध्य प्रदेश में सड़क विकास के लिये विश्व बैंक सहायता

745. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **जल-भतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मध्य प्रदेश सरकार की इस वर्ष सडक विकास के लिये विश्व बैंक से कुल कितनी ऋण सहायता प्राप्त होने की संभावना है ,

(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकार किये जाने की संभावना है ; और

(ग) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

जल संसाधन मंत्री, साथ में जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (ग) 75.12 करोड रु० की अनुमानित लागत से मध्य प्रदेश मे राष्ट्रीय राजमार्ग-3 पर इन्दौर देवास खड मे 19.0 कि० मी० लम्बाई को चार लेन का बनाने तथा इन्दौर बाई पास (लम्बाई 31 4 कि० मी) के निर्माण के प्रस्ताव को सभावित सहायता के लिए विश्व बैंक के समक्ष पेश किया गया है । ऋण के लिए अभी विचार-विमर्श किया जाना है । अत. परियोजना के अनुमोदन की संभावित तारीख और व्यय के समय के बारे मे कहना समयपूर्व है ।

दूसरे देशों में भारतीय वाणिज्य दूतावास

746. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन देशो मे भारतीय वाणिज्य दूतावास कार्य कर रहे हैं ;

(ख) उन दूतावासो द्वारा विशेष रूप से व्यापार आदि को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या कार्य किये जा रहे है ;

(ग) उन दूतावासो मे नियुक्त अधिकारियों के नाम क्या हैं, साथ ही वे वहां कितनी-कितनी अवधि से हैं ?

विदेश मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) प्रमुख कोंसलावासों, कोंसलावासो तथा सहायक हाई कमीशनो (जो राष्ट्र-मंडल देशो में कोसली कार्यालयों के पदनाम है) की सूची अनुपत्र मे दी गई है जिसमें केन्द्रों तथा देशों का ब्यौरा भी है । [देखिये परिशिष्ट 156, अनुपत्र सं० 15]

(ख) भारत के प्रमुख कोसलावास/कोंसलावास/सहायक हाई कमीशन अनिवार्य रूप से कोसली कार्यालय है जिनसे उनके कोसली अधिकार क्षेत्र के क्षेत्र मे भारतीय राष्ट्रिकों तथा भारतीय मूल के लोगो के हितो और आवश्यकताओ को पूरा करने की उम्मीद की जाती है । जहा आवश्यक होता है भारत के प्रमुख कोंसलावासों/कोंसलावासों/सहायक हाई कमीशनों का इस्तेमाल उनके कोसली प्रत्यावर्तन क्षेत्र मे तथा प्रत्यावर्तन के देश में भारतीय राजदूत/हाई कमीशन के समन्वय से वाणिज्यिक, सास्कृतिक तथा प्रचार कार्य करने के लिए भी किया जाता है । इस प्रकार व्यापार का संवर्धन भी भारत के प्रमुख कोंसलावासों/कोंसलावासो/सहायक हाई कमीशनो के कार्यों में शामिल है ।

(ग) वहा तैनात राजनयिक अधिकार्यों की सूची केन्द्रो मे उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख के साथ अनुबंध मे दी गई है ।[देखिये परिशिष्ट 156, अनुपत्र स० 15]

Irrigation projects in Tamil Nadu with Central Assistance

747 SHRI R. T, GOPALAN: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state·

(a) the number of irrigation projects undertaken wtih Central assistance under irrigation Development Programme in Tamil Nadu during the Seventh Plan period; and

(b) the progress made and assistance given by the Central Government in this regard so far?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF SURFACE